भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 293

20 जुलाई, 2021

"एथेनॉल का उत्पादन"

293. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने के अलावा चावल, मक्का और जौ जैसे विभिन्न पशु आहारों से एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एथेनॉल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से कृषि आधारित पशु आहार से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना/नीति आरंभ की है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्टॉक से एथेनॉल के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में चावल आवंटित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने और देश में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी हां। गन्ना और अन्य शर्करा युक्त पदार्थों (जैसे शुगर बीट, स्वीट सोरघम आदि) के अलावा विभिन्न प्रकार के फीडस्टॉक्स जैसे कृषि अवशेष (राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉल्क, कॉर्न कॉब, सॉ डस्ट, खोई आदि); स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू आदि; क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों जैसे गेहूं, टूटे चावल आदि; और चावल जैसे खाद्यान्नों से एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है।

(ख): एथेनॉल के उत्पादन के लिए कृषि आधारित फीडस्टॉक्स के प्रयोग और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को निर्धारित लाभकारी मूल्यों पर इसकी आपूर्ति करने से चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों को किसानों की आय बढ़ाने और किसानों के बकाया का समय पर भुगतान करने में भी मदद मिली है।

(ग): देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने ब्याज छूट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए समय-समय पर ब्याज छूट स्कीम अधिसूचित की है। हाल ही में सरकार ने शीरा आधारित/अनाज आधारित/ड्यूअल-फीड डिस्टिलरियों की स्थापना करने या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 14.1.2021 को एक संशोधित ब्याज छूट स्कीम अधिसूचित की है, जिसके तहत सरकार एक वर्ष की आस्थगन अवधि सहित पांच वर्षों की अवधि के लिए 6% या बैंकों से उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर बैंकों द्वारा लगाए जा रहे ब्याज की दर के 50%, जो भी कम हो, पर ब्याज में छूट प्रदान कर रही है।

(घ): भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। एथेनॉल जैसे घरेलू जैव-ईंधन, आयातित जीवाश्म ईंधनों पर देश की निर्भरता को कम करते हैं; इसके अलावा इसका उपयोग वाहनों के प्रदूषण को कम करता है, किसानों की आय में वृद्धि करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर लाता है जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से शीरा/गन्ना और क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से किया जा रहा है; परंतु इन फीडस्टॉक्स की उपलब्धता एवं एथेनॉल उत्पादन की मौजूदा क्षमता सरकार द्वारा निर्धारित ब्लेंडिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के लिए फ्यूल ग्रेड एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार डिस्टिलरियों को एफसीआई के पास उपलब्ध अधिशेष चावल; और मक्के से एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए स्टॉक में एफसीआई चावल पर्याप्त मात्रा में है और यह मात्रा इसी प्रकार बनी रहेगी क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान/चावल की खरीद प्रत्याशित स्तर पर हो रही है। एथेनॉल के उत्पादन हेतु दिसंबर 2020-नवंबर 2021 की अवधि के दौरान 78844 टन एफसीआई चावल 20 रुपए/कि.ग्रा. एक्स-एफसीआई गोदाम मूल्य की दर से डिस्टिलरियों को आवंटित किया गया था जिसमें से डिस्टिलरियों ने दिनांक 14.7.2021 तक 22716 टन उठा लिया है।

(ङ): एथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन/उपयोग को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में एथेनॉल मूल्य निर्धारण के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित करना; एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त करना; उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाना; पेट्रोल के साथ ब्लेंडेड एथेनॉल (ईबीपी) कार्यक्रम हेतु प्रयुक्त एथेनॉल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) को 18% से घटाकर 5% किया जाना; जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 अधिसूचित करना; एथेनॉल खरीद के लिए कच्चे माल का क्षेत्र विस्तार करना; एथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और विस्तार के लिए ब्याज छूट स्कीम लागू करना; अप्रैल 2019 में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह को छोड़कर पूरे भारत में ईबीपी कार्यक्रम का विस्तार करना; और 1 अप्रैल, 2023 से पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल ब्लेंड करने हेतु ओएमसी को अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी करना शामिल हैं।

******